दुनिया सेहतमंद चाहते हैं तो जंगली जानवरों को छोड़ दें अकेला

यह बात दुनिया में आम हो चुकी है कि चीन के सी फूड मार्केट से घातक कोरोना वायरस दुनिया में फैला। चीन के मीडिया के अनुसार वमगाडड़ सरीदने वाली एक महिला दुनिया की पहली मरीज (जिसे जीरो पेशेंट नाम दिया गया) थी। उसे शुरुआत में हल्की-सर्दी खांसी हुई, एक-दो दिन आराम करने के बाद वह फिर से सी फूड मार्केट में आई और दुबारा को धीरे-धीरे कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। यदि आपको चीन के मीडिया की इस रिपोर्ट पर विश्वास न हो तो भी यह बात पूरी तरह सच है कि जंगली जानवरों से इंसान की छेड़छाड़ उसे ही बहुत भारी पड़ रही है।

8 गुना अधिक वायरस इंसानों तक पहुंचाते हैं चूहे-बिल्ली जैसे घरेलू जानवर, जंगली जानवरों के मुकाबले

जर्नल प्रोसेडिंग ऑफ रॉयल सोसायटी में प्रकाशित शोध के मुताबिक जानवर हर वर्ष बड़े पैमाने पर इंसानों को जान ले रहे हैं और दुनिया को अरबों डॉलर की आर्थिक चपत लगा रहे हैं। यूसी डेविस स्कूल ऑफ वेटनरी साइंस के वन हेल्थ इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉ. क्रिस्चियन क्रुयडेर के मुताबिक कोरोना की तरह की बीमारियां जानवरों के प्राकृतिक निवास और रहन-सहन में इंसान के सीधे हस्तक्षेप का नतीजा है।

2,90,000
जानवरों के प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं

30%
कम से कम होना चाहिए वन क्षेत्र किसी भी देश में

दो अरब बीमार और दो करोड़ मारे जाते हैं

आप कोरोना वायरस को ही खौफनाक मानते हैं तो यह आंकड़ा पढ़ लें। फॉरेन वायरस (जो घरेलू और जंगली जानवरों से इंसानों में आए) के कारण हर साल दुनियाभर में दो अरब लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से दो करोड़ लोग मारे जाते हैं। ये वायरस इंसानों को एचआइवी से लेकर इबोला तक से मार रहे हैं, इसका एक ही कारण है इंसानों का जानवरों की प्राकृतिक जीवनशैली में हस्तक्षेप।

पत्ते हों या पूछे, बन जाते हैं मौत के फरिश्ते

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने 1940 को आधार वर्ष मानते हुए अपने शोध को अंजाम दिया। नतीजे निश्चित रूप से डराने वाले हैं। कुत्ते, बिल्लियों, भेड़ों जैसे घरेलू जानवरों के साथ ही बंदरों-चूहों ने भी इंसान को काफी क्षति पहुंचाई है। जंगली जानवर इंसानों से दूर थे लेकिन, इंसान ने ही कभी विकास, कभी जानवरों के व्यापार और कभी उन्हें बचाने के नाम पर जंगली जानवरों व अपने बीच मौजूद दूरी को खत्म कर दिया। प्लेग जैसी महामारी ने तो दुनिया का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। वहीं यीन रोग एचआइवी बंदरों से इंसानों में आया।

चमगादड़ साबित हुए हैं खतरनाक

चमगादड़ पिछले तीन दशक से काफी परेशान कर रहे हैं। सार्स हो या निपा वायरस या फिर इबोला सभी ने बड़े पैमाने पर इंसानों की जान ली। हालांकि इन सभी पर इंसानों ने कंट्रोल पाया और ये ज्यादा क्षेत्र आधारित बीमारियां साबित हुईं। इबोला के कारण दो वर्ष तक पूरा अफ्रीका महाद्वीप खतरे में रहा था। अब जाकर इसका वैक्सीन और इलाज खोजा जा सका है।

पूर्ण प्रतिबंध

कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 200 से अधिक वाइल्ड लाइफ संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग की है कि जंगली जानवरों के व्यापार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। परंपरागत चिकित्सा के नाम पर दी जानी वाली किसी भी छूट पर भी पाबंदी लगे। अहम है कि चीन में शेरों से लेकर बेल तक का इस्तेमाल परंपरागत चिकित्सा के लिए किया जाता है और इसी आधार पर इनका व्यापार कानूनी बना दिया गया है। चीन का जानवरों का बाजार दुनियाभर में बदनाम है। भारतीय बाघों की भी चीन के दवा बाजार में बहुत मांग है। इसके कारण भारतीय बाघों का बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है।

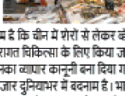

जंगली जानवरों से इंसानों में आए 142 वायरस

वर्ष 1940 के बाद से इंसानों में 142 वायरस आ चुके हैं, कुछ ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो कुछ ने कम। कई को इंसानी शरीर ने स्वीकार कर लिया, तो कई के तोड़ हमने खोज निकाले लेकिन, अब भी कई बहुत जानलेवा हैं, जिनसे बचाव ही इलाज है। चाहे वो कोरोना हो या एचआइवी। चूहे, बंदर और चमगादड़ इंसानों में फैलने वाले 75 फीसद वायरस के लिए जिम्मेदार हैं।

इन वायरसों ने खाया है कहर

इबोला, एचआइवी, बोर्निन टीबी, रेबिज, लेप्टोस्पिरोसिस, स्वाइन फ्लू, हंटा वायरस, पीजन फ्लू, वेस्ट नाइल इंफेक्शियस, साइटोडोमाइकोसिस, वाइट नोस सिंड्रोम, एबोला, डोबिल फेस, कैनिन डिस्टेंपर, क्लेमीडिया, सारकोप्टिक मेंगे, प्लेग, ई-कोलाई।

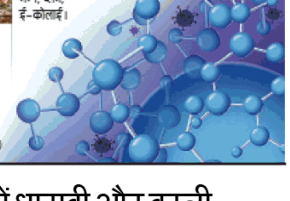

पर्यटकों के लिए जलियांवाला बाग 15 जून तक रहेगा बंद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना के चलते जलियांवाला बाग के नवीनीकरण का काम समय से पूरा न हो पाने के चलते सरकार ने इसे अब 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है। इससे पहले इसे नवीनीकरण से जुड़े कार्य के लिए 12 अप्रैल तक के लिए ही बंद किया गया था। इसे 13 अप्रैल 2020 को नरसंहार के शताब्दी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए खोला जाना था, लेकिन सरकार ने कार्य पूरा होने तक यानि 15 जून तक बंद रखने का फैसला लिया है।

संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक, देश फिलहाल जलियांवाला नरसंहार की शताब्दी वर्ष बना रहा है। इसके तहत इसका नए सिरे से संवारने का काम चल रहा था। जिसे 12 अप्रैल तक पूरा कर लेना था, लेकिन कोरोना के चलते यह काम समय पर नहीं हो सका। योजना के मुताबिक, इसे नवीनीकरण के बाद 13 अप्रैल को खोला जाना था। बता दें कि 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। इस दिन यहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं।

पूरी तरह स्वस्थ हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' वाले तन्मय वेकारिया

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : सोनी सब पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के बाघा यानी तन्मय वेकारिया को लेकर खबरें थीं कि वह सेल्फ क्वारंटाइन में हैं। हालांकि, दैनिक जागरण से बातचीत में तन्मय ने स्पष्ट किया है कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। दरअसल, कांदिवली वेस्ट में तन्मय की बिल्डिंग में नहीं, बल्कि उनकी सोसाइटी में एक ही परिवार के तीन लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। सात अप्रैल को पहला मामला सामने आने के बाद उनकी सोसाइटी को सील कर दिया गया था। तन्मय ने कहा, 'सोसाइटीवासियों को 14 दिनों के लिए घरों में ही रहने को कहा गया है। पिछले 22 दिनों से हम अपने घरों में ही हैं। जिस परिवार के सदस्य को कोरोना संक्रमण हुआ है, मैं उनके संपर्क में नहीं आया हूं।'

जनमत मुद्दा

क्या पूर्व में फैला हुई महामारियों से लड़ने की इंसानी जिजीविषा कोरोना महामारी को समूल नाश में बुनियाद के लिए संयत बनी हुई है?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

पंजाब ने एक मई तक बढ़ाया कर्फ्यू

अहम कदम ▶ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जताई कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका

राजस्थान व उत्तराखंड ने दिए 15 दिन तक लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत

जेएनएन, नई दिल्ली

कोविड-19 वायरस के संक्रमण से भयावह होते हालात को देखते हुए ओडिशा के बाद दूसरे राज्य भी अपने स्तर पर एहतियाती पाबंदियों को आगे बढ़ा रहे हैं। कम्युनिटी संक्रमण की आशंका से पंजाब सरकार ने एक मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया है और राजस्थान व उत्तराखंड की सरकारें लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिए हैं कि हॉटस्पॉट बने कुछ इलाकों में कर्फ्यू लागू रखा जाएगा और अन्य क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियां खत्म करने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। डॉक्टरों व अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों वाली उच्चस्तरीय कमेटी हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद ही कोई फैसला होगा। इससे पूर्व वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आगामी महीने में हालात गंभीर चुनौतियों भरे हो सकते हैं। ऐसे हालात में किसी भी राज्य के लिए लॉकडाउन को खत्म करना आसान नहीं होगा। गुरुवार को 27 पॉजिटिव मामले आए, जो एक दिन में सर्वाधिक हैं। यह संकेत है कि राज्य कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ जा सकता है। स्थिति और गंभीर हो सकती है।

कैप्टन अमरिंदर सिंह — फाइल

पंजाब में 87 और देश में 58 फीसद लोग हो सकते संक्रमित : कैप्टन ने चंडीगढ़ पीजीआइ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पंजाब में 87 फीसद लोगों और देशभर में 58 प्रतिशत लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की आशंका है। इन दावों पर विवाद छिड़ा तो उनके मीडिया सलाहकार रवीन दुकराल ने ट्वीट करके कहा कि कैप्टन ने जिस आकलन का उल्लेख किया है, वह पीजीआइ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स डॉ. शंकर प्रिंजा और उनकी टीम की एक रिपोर्ट पर आधारित है। हालांकि शाम को पीजीआइ ने इसका खंडन करते हुए कहा कि कम्युनिटी मेडिसिन विभाग ने ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है।

लॉकडाउन से अलग है कर्फ्यू

लॉकडाउन में लोगों से घर में रहने की अपील की जाती है, लेकिन जरूरी सेवाएं बंद नहीं होती। बैंक, डेयरी, दवा, राशन, फल-सब्जी व अन्य जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहती हैं। इसका पालन नहीं करने पर जेल हो सकती है। वहीं, कर्फ्यू इससे आगे का कदम है। इसमें लोगों को घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। छूट बहुत कम देर के लिए दी जाती है। अति आवश्यक सेवा ही चालू रहती है। अति गंभीर स्थिति में देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए जा सकते हैं। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी और जुर्माना हो सकता है।

मुंबई में धारावी और वरली-कोलीबाड़ा में घर-घर जांच शुरू

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- जुमे की नमाज को लेकर झुग्गी बस्ती में चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस
- लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की भी ली जा रही है मदद
- अजीत पवार ने बारामती में भीलवाड़ा पैटर्न अपनाने को कहा

महाराष्ट्र खासकर मुंबई में कोरोना महामारी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महानगर ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में कोरोना के बढ़ते मामलों में राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए धारावी समेत कुछ अन्य इलाकों में घर-घर की जांच शुरू कर दी गई है।

धारावी एवं वरली कोलीबाड़ा सहित कई इलाकों में घर-घर जांच की जांच में कोरोना जैसे लक्षण वाले 292 लोग पाए गए हैं। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों के नजदीक प्रतिबंधित क्षेत्रों में रहनेवाले सभी लोगों की जांच के दौरान 60 फीसद लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं।

मुंबई की सबसे सघन झुग्गी बस्ती धारावी में घर-घर जांच की मुहिम शुक्रवार को भी जारी रही। इस क्षेत्र में 11 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए। इनमें से दो व्यक्ति दिल्ली के तबलीगी जमात से लौटे थे। इस इलाके में 45 फीसद से अधिक आबादी मुस्लिम समुदाय की है। शुक्रवार की सामूहिक नमाज पर प्रतिबंध के लिए धारावी में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई थी। पुलिस ने धारावी के प्रमुख मार्गों पर मार्च भी किया। अत्यंत संकरी गलियों वाली धारावी की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इन प्रयासों का असर धारावी पर दिखाई दिया और सड़कों पर सन्नाटा नजर आया।

मुंबई में कोरोना रोगियों की सर्वाधिक संख्या वाली झोपड़पट्टी वरली कोलीवाड़ा में भी घर-घर जांच का सिलसिला चल रहा है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने गृह क्षेत्र बारामती लोकसभा क्षेत्र में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए भीलवाड़ा पैटर्न अपनाने के निर्देश दे दिए हैं।

विदेश से भारतीयों को लाने पर फैसला हालात की समीक्षा के बाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर 20,400 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को भारत से निकाला गया है। जबकि विदेश से भारतीयों को लाने का फैसला हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।

रोजाना की जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव दम्मू रवि ने बताया, 'कई देशों की सरकारों ने अनुरोध किया था। लिहाजा हमने गुरुवार तक 20,473 विदेशी नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। यह एक लगातार जारी प्रक्रिया है। कुछ सवाल विदेश में रह रहे भारतीयों के बारे में आए हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसमें हम निश्चित जवाब नहीं दे सकते क्योंकि लॉकडाउन अभी जारी है। हमें हालात की समीक्षा करने की जरूरत है... इसका फैसला सरकार करेगी कि अन्य देशों से भारतीयों को वापस लाने का प्रबंध हम कैसे करें। इन सभी देशों में हमारे राजदूत और उच्चायुक्त विदेश में सभी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में हैं और उन्हें हर सहायता प्रदान कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के कोविड नियंत्रण कक्ष में हेल्पलाइंस भी सक्रिय हैं, टीमें इन मामलों में मार्गदर्शन कर रही हैं। स्थिति नियंत्रण में है। उनकी वापसी के बारे में हम बाद के चरण में समीक्षा करेंगे।'

देश में 37,978 राहत शिविर संचालित : गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि नौ अप्रैल तक विभिन्न राज्य सरकारों से मिली जानकारी के मुताबिक देशभर में 37,978 आश्रय और राहत शिविर संचालित हैं जिनमें प्रवासी कामगारों और अन्य जरूरतमंद लोगों को ठहराया गया है। इनमें से 34 हजार राहत शिविरों को राज्य सरकारों और 3,978 को गैर सरकारी संगठनों ने स्थापित किया है। देश में 26,225 खाद्य शिविर संचालित हैं जहां एक करोड़ से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें से 14,799 को राज्य सरकारें और 11,426 शिविरों को गैर सरकारी संगठन संचालित कर रहे हैं। करीब 16.5 लाख कामगारों को उनके नियोक्ताओं और उद्योगों ने आश्रय एवं भोजन उपलब्ध कराया है।

अब तक 1,44,910 सैंपलों की जांच

प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 146 लैब कार्यरत हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की 67 लैब को भी जांच की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि गुरुवार रात नौ बजे तक कुल 1,44,910 सैंपलों की जांच की गई थी।

कोरोना संदिग्ध गर्भवती की मौत के मामले की जांच हो : महिला आयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने नौ महीने की एक गर्भवती की मौत के मामले में जांच की मांग की है। महिला कोरोना संदिग्ध थी और उसे इलाज के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 27 वर्षीय गर्भवती को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसके बाद उसे अलग-अलग अस्पतालों में ले जाना पड़ा। इस दौरान उसे नालासोपारा से मुंबई के बीच 70 किलोमीटर का सफर करना पड़ा। अगले दिन दोपहर में महिला की मौत हो गई और गर्भस्थ शिशु को भी नहीं बचाया जा सका।

इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए महिला आयोग ने मामले की जांच की मांग की है। महिला आयोग ने ट्वीट किया, 'महाराष्ट्र में नौ महीने की एक गर्भवती की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़ा। संदेह है कि उसे कोरोना संक्रमण था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और इससे भी दुखद रहा कि उसे अस्पतालों तक पहुंचने और इलाज पाने के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा।'

अब छत्तीसगढ़ सरकार भी सोशल के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग की करेगी बात

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दैनिक जागरण और उसके सहयोगी प्रकाशन नईदुनिया की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि दैनिक जागरण समूह सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) शब्द का प्रयोग कर रहा है, जोकि सही है। अब हमारी सरकार भी इसी शब्द का उपयोग करेगी।

गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का प्रयोग लोग कर रहे हैं, लेकिन दैनिक जागरण समूह ने सबसे पहले इस शाब्दिक त्रुटि को सुधारा था। दैनिक जागरण और नईदुनिया ने फिजिकल डिस्टेंसिंग (शारीरिक दूरी) लिखना शुरू किया। सीएम बघेल ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा है कि यह अच्छी सोच है।

सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक दूरी है। हम अपने ही समाज के लोगों को अपने से कैसे दूर कर सकते हैं। इसकी जगह शारीरिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस की जरूरत है। इस शब्द को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अब अपना लिया है।

'दैनिक जागरण' की पहल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया स्वागत

भूपेश बघेल — फाइल

कोरोना के कारण दुनिया के ज्यादातर उद्योग-धंधे ठप पड़े हैं। शेयर बाजारों में जबरदस्त गिरावट का दौर है और कई लोगों के सामने अभी से रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यह स्थिति बद से बदतर हो सकती है। साथ ही आर्थिक विश्लेषकों ने आशंका जताई है कि दुनिया गंभीर आर्थिक मंदी का शिकार हो सकती है। ऐसे वक्त में ऑक्सफैम की चेतावनी ने और चिंता बढ़ा दी है। ऑक्सफैम के अनुसार कोविड-19 संकट से निपटने के लिए गंभीर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली मंदी दुनिया के करीब आधे अरब लोगों को गरीबी में धकेल देगी। यह दुनिया की 8 फीसद आबादी है।

कई देशों पर बहुत बुरा प्रभाव

किंग्स कॉलेज लंदन और ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक शोध किया है, जिसमें उन्होंने विश्व बैंक की गरीबी रेखा पर 1.90 डॉलर, 3.20 डॉलर और 5.50 डॉलर प्रति दिन के आधार पर वैश्विक मौद्रिक गरीबी पर कोरोनो वायरस के अल्पकालिक प्रभाव का अनुमान लगाया है। वैश्विक स्तर पर प्रगति के एक दशक तक के विश्लेषण के अनुसार 1990 के बाद पहली बार सभी तीन परिदृश्यों के तहत वैश्विक गरीबी का स्तर बढ़ेगा। इसका असर दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, सब-सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व में और भी बुरा होना तय है, जहां यह 30 साल तक की तरक्की को खत्म कर सकता है।

यह होगा परिणाम

सबसे गंभीर परिदृश्य में आय में 20 फीसद की गिरावट शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त 54 करोड़ लोग प्रति दिन 5.50 डॉलर (417 रुपये) की विश्व बैंक की गरीबी सीमा से कम कमाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि संकट के दौरान विकासशील देशों को समर्थन देने के लिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है और अफ्रीका के करीब आधे रोजगार खो सकते हैं।

संकट से निपटने की तैयारी

अगले सप्ताह ऋण राहत पर चर्चा के लिए जी-20 देशों के मंत्रियों, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की बैठक होगी। ऑक्सफैम ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आर्थिक पतन को रोकने के लिए बताई गई राशि जुटाने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया है। धन जुटाने के संभावित उपायों में 1 ट्रिलियन डॉलर के ऋण को तत्काल रद्द करना शामिल हो सकता है।

आधे अरब लोगों को गरीबी में धकेल सकता है कोरोना संकट

कोविड-19 के कारण 20 फीसद आय में गिरावट से अतिरिक्त लोग गरीबी में आएंगे

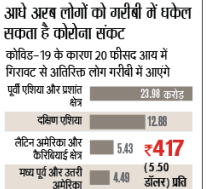

राहत

योगी ने 4.81 लाख गरीबों के खाते में भेजे एक-एक हजार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरों में दैनिक कार्य कर जीवनयापन करने वालों की शुक्रवार को आर्थिक मदद की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणी के 4.81 लाख से अधिक गरीबों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि भेजी। यह धनराशि स्ट्रीट वेंडर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ई-रिक्शा चालक एवं मंडी में काम करने वाले पल्लेदारों को दी गई है।

मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित इन शहरी गरीबों की 48.17 करोड़ रुपये से अधिक की मदद की। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास पांच कालिदास मार्ग से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग जिलों के लाभार्थियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को भोजन और भरण-पोषण भत्ता सरकार मुहैया करा रही है। इसमें रेहड़ी, ठेला, खोमचा, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदार शामिल हैं। इन्हें एक-एक हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता दिया जा रहा है।

योगी ने कहा कि इससे पहले सरकार ने 35 लाख मजदूरों को भरण-पोषण भत्ता दिया था। 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे जा चुके हैं। मनरेगा मजदूरों का मानदेय बढ़ाकर भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में 7.65 करोड़ से ज्यादा अंत्योदय योजना, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं दिहाड़ी मजदूरों को निःशुल्क राशन भी मुहैया कराया जा रहा है।

स्ट्रीट वेंडर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदार है शामिल

योगी आदित्यनाथ — फाइल

किसानों को तीन माह तक मिलेंगे दो-दो हजार

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 2.34 करोड़ किसानों को तीन माह तक दो-दो हजार रुपये देने की व्यवस्था सरकार ने की है। जनधन खाते में प्रति माह तीन महीने तक 500 रुपये दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तीन महीने तक मुफ्त रसोई गैस मुहैया कराई जा रही है। इस संकट में केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। हर जिले में कम्युनिटी किचन के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।